भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1548

09.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र का प्रदर्शन

1548. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भारी उद्योग क्षेत्र के उत्पादन, रोजगार और निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कोई गिरावट या वृद्धि देखी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे 'भेल' आदि का निजीकरण या विनिवेश करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कर्मचारियों और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग उपकरणों और विभिन्न उप-क्षेत्रों के संबंध में उत्पादन डेटा वर्ष 2020-21 में 2,66,672 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5,69,900 करोड़ रुपये हो गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**उप-क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	मशीन टूल्स	6602	9307	11956	13571	14286
2	डाई, मोल्ड और प्रेस टूल्स	12294	13128	13915	15600	18400
3	टेक्सटाइल मशीनरी	5093	11658	14033	14639	10461
4	प्रिंटिंग मशीनरी	10058	13215	16107	23479	29716
5	अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी	29021	28674	37551	73000	80750

6	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	3710	3850	3912	4310	4827
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	10250	12210	13203	13863	15249
8	प्रक्रिया संयंत्र उपकरण	21938	24000	23415	27396	31505
9	भारी इंजीनियरिंग उपकरण	167706	219158	258832	302900	364706
	कुल	**266672**	**335200**	**392924**	**488758**	**569900**

(स्रोत: उद्योग संघ अर्थात् आईईईएमए, आईएमटीएमए, टीएजीएमए, टीएमएमए, आईपीएएमए, आईसीईएमए, पीएमएमएआई, एएफटीपीएआई और पीपीएमएआई)

चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए भारी उद्योग मंत्रालय देश में भारी उद्योगों में नए रोजगार सृजन और निवेश के संबंध में कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखता है।

(ग और घ): वर्तमान में, बीएचईएल के विनिवेश के लिए भारी उद्योग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के संबंध में निम्नलिखित पर अपनी 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की:

- ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड (बी एंड आर) का विनिवेश।
- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की इकाइयों का, जहां कानूनी रूप से अनुमति हो, विनिवेश किया जाएगा।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) का समान स्थिति वाले सीपीएसई के साथ विलय द्वारा विनिवेश।

बीएंडआर और ईपीआईएल के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी। हालाँकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। सीसीआई की इकाइयों की विनिवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि इन्हें रणनीतिक बिक्री के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

***